वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एन टी सी द्वारा सामना की जा रही कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कन्ट्रोल के कपड़े का समग्र उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित नहीं किया गया है । फिर भी हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है । वर्ष 1990-91 के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन लक्ष्य 600 मिलियन वर्ग मीटर है जब कि इसकी तुलना में वर्ष 1984-85 में यह 360 मिलियन वर्ग मीटर था ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना

1308. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश मे राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितनी धनराशि के खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन मिलों का आधुनिकीकरण हो जाने के बाद उन्हें होने वाले वार्षिक लाभों की बाबत अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार लगाये गये अनुमान की राशि कितनी है तथा इन मिलों के आधुनिकीकरण तथा अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली धनराशि के इन मिलों द्वारा अर्जित लाभ की राशि में से, कितने वर्षों में वसूल कर लिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है । फिर भी सरकार एन टी सी की मिलों का आधुनिकीकरण क्रियान्वित नहीं करती । सरकार एन टी सी को मार्जिन धनराशि प्रदान करने के लिए बाजार व्यवस्था करती है ताकि वह अपनी आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सके ।

अभी तक वित्तीय संस्थानों ने 20 एन टी सी मिलों के लिए आधुनिकीकरण प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिन पर 90.87 करोड़ रु. व्यय होंगे । इसके अतिरिक्त एन टी सी ने वित्तीय संस्थानों के अनुमोदन के लिए 122.61 करोड़ रु. के परिव्यय वाली आधुनिकीकरण योजना भी प्रस्तुत की है ।

वित्तीय संस्थान आधुनिकीकरण प्रस्तावों की जांच करते हैं तथा उन्हें प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है जिन्हें अर्थक्षम पाया जाता है तथा जिनसे एक निर्धारित अवधि में मिलों द्वारा लाभ कमाने में सहायता मिलती है ।

Premises leased out to branches of Andhra Bank in Bombay

1039. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some branches of Andhra Bank in Bombay are still occupying the premises leased out to them even after the expiry of the lease period;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to renew the lease agreements with the lessors/landlords in accordance with the guidelines issued by Government to all the nationalised banks in this regard; and

(d) if so, by when all such cases are likely to be settled?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Andhra Bank has reported that none of its branches in Bombay is occupying premises after the expiry of the lease period.

(b) to (d) Do not arise.

Spending on food and fertilizer subsidies

1040. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how much amount has been spent on providing subsidy to fertilizers and food in the year 1985-86 to 1989-90 and from 1.4.90 to 30.6.90;

(b) whether there is any proposal to stop such subsidies; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) The amount spent on providing subsidies to fertilizers and food are as follows:

(Rs. in crores)

Year	Fertilizer	Food
1985-86 . . .	1924	1650
1986-87 . . .	1897	2000
1987-88 . . .	2164	2000
1988-89 . .	3201	2200
1989-90 . . .	4545	2476
1-4-90 to 30-6-90 .	1086	414

(b) There is no proposal to stop these subsidies.

(c) Does not arise.

देश में लोहा तथा इस्पात मिलें

1041. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोहा तथा इस्पात रि-रोलिंग मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक मिल को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने मीटर-टन माल सप्लाई किया जाता है;

(ग) राजस्थान में उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय कच्चा माल दिया जा रहा है तथा प्रत्येक मिल को कितना-कितना माल दिया जा रहा है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रि-रोलिंग कच्चे माल का कितना-कितना कोटा निश्चित किया गया तथा कितना कितना माल सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) :(क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । **(नीचे देखिये)**

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात सामग्री की सप्लाई के लिए कोई पद्धति नही है ।

(घ) पुनर्बेलन मिलों को इस्पात सामग्री की सप्लाई के लिए कोई "कोटा" निर्धारित नहीं किया गया है ।